‘शहर की खेती’

भारत के शहरों में खेती पर एक राष्ट्रीय जन सम्मेलन

11-12 अप्रैल, 2020

IRD कांफ्रेंस सभागार, आईआईटी दिल्ली**,** हौज़ ख़ास, दिल्ली-16**.**

सन्दर्भ

हर मायने में हम एक गहरे संकट की स्थिति से घिरे हुए हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, महासागरों का पानी तेजाब में बदल रहा है, बारिश अप्रत्याशित होती जा रही है, बढ़ते हुए शहरों में तपते हुए द्वीप बन रहे हैं, जनहित के नाम पर समुदायों को बेदखल किया जा रहा है, और हिफाज़त के नाम पर जंगली जीवन और जैवविविधता का सत्यानाश हो रहा है। इस सबके बीच दुनिया पर हुक्म चलाते कॉर्पोरेट वर्ग का धरती को तहस-नहस करने का अभियान जारी है और “लोकतांत्रिक” तरीके से चुने हुए तानाशाह उदारपंथी लोकतंत्र की सभी संस्थाओं से खिलौने की तरह खेल रहे हैं। प्रकृति और समुदाय के साथ सीधे टकराव पर टिकी हुई मौजूदा राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था ने हमें भोजन, ऊर्जा, घर, पर्यावरण, आर्थिकी का मिलाजुला संकट थमा दिया है, जिसके चलते लोगों में इस बात को लेकर घबराहट का होना वाजिब है कि इंसान के अस्तित्व पर खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

शहर इस बदलाव के केंद्र में हैं। दुनिया में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है लेकिन ये शहरीकरण टिकाऊ नहीं है। शहर की योजना बनाने वाले यथार्थ से अलग-थलग एक ही दिशा में सोचते हुए सिर्फ आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने की योजना बनाते हैं। आर्थिक वृद्धि मुनाफा बढ़ने और कुछ लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पूँजी इकठ्ठा होने का पर्याय है। इसके लिए शासक वर्ग को ज्यादा से ज्यादा संसाधनों पर एकाधिकार चाहिए। इसलिए शहर ऊपर, नीचे, बाहर- सब तरफ बढ़ रहे हैं। सामान, ऊर्जा, और सूचना का प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर आज जितना नहीं कभी नहीं था। इसके चलते जो प्रक्रियाएँ लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं और जिस वृहद् तंत्र के वे हिस्सा हैं, लोगों की समझ और सामाजिक जीवन से परे हो गए हैं। ये बदलाव धन संचय की पूँजीवादी प्रक्रिया के तहत आया है और साथ ही इस बदलाव से धन संचय और तेज हुआ है। धन संचय की वर्तमान प्रक्रियाओं में से सबसे अहम है वित्तीकरण और निजीकरण जिसके जरिये सामान्य जीवन के हर पक्ष पर कॉर्पोरेट को नियंत्रण मिल जाता है। हमारी रोजमर्रा की ज़िन्दगी का हर हिस्सा हमारी निगरानी से इतना दूर हो गया है कि वो असलियत से अलग हो गया है। जीवन के स्वाभाविक स्वरुप और उसको सहारा देने वाली सामाजिक-पारिस्थितिक प्रक्रियाओं से दूर होते शहर और शहर के जीवन की नीरसता से घिरा इंसान पूँजीवादी आधुनिकता की जादुई बनावट में अपना बयान पा रहा है।

दुनिया की खाद्य व्यवस्था आज के समय में कॉर्पोरेट-द्वारा नियंत्रित और बेहद वित्तीकृत (सरल मायने में ‘यथार्थ से दूर’) है और चंद लोगों के दाँव खेलने से ये तय हो सकता है कि बाकी लोग भोजन पाते हैं या नहीं, और जो पाते हैं वो किन दामों पर। शहर में खाने की आपूर्ति में दूर गाँवों और दूसरे देशों में होने वाली उपज का हिस्सा बढ़ रहा है क्योंकि शहर और उसके आसपास की जमीन तो रियल एस्टेट और मुनाफाखोरी के बाकी उपक्रमों में खपाई जा रही है। तरक्की के नाम पर न सिर्फ शहर का पानी, हवा और रहने की जगहें दूषित की जा रही हैं बल्कि शहर में जो खाना आता है, उसका भी पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। दिल्ली जैसे शहर में दसियों हजारों टन कचरा लैंडफिल (जो अब कचरे के पहाड़ में तब्दील हो चुके हैं) में रोज जमा हो रहा है और शहरी पर्यावरण को हद से ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन अगर सिर्फ आस-पास ही नज़र घुमा के देख लें तो पता चल

जायेगा कि इस प्रक्रिया की रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में कोई जगह नहीं दिखती। जैसा हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, वो उसी तंत्र द्वारा तय हो रहा है जिसके हिसाब से हमें अपनी ज़िन्दगी को किसी न किसी हद तक ढालना ही पड़ रहा है। बल्कि एक वर्ग इस तंत्र के हिसाब से सिर्फ खुद को ढालने के साथ-साथ इसको अपने फायदे के लिए मजबूत भी कर रहा है। मसलन, शहर और आस-पास के इलाके में भू-उपयोग में बदलाव करके सरकारें उदारीकरण के एजेंट की तरह काम करती हैं और खेती-लायक जमीन को वैश्विक स्तर पर खरीद-फरोख्त के लिए उपलब्ध करा देती हैं। इस नीतिगत बदलाव से पारंपरिक रूप से खेती पर निर्भर रहने वाले समुदाय में भी जमीन के उपयोग में रूचि घटी है और जमीन के दाम से मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति मजबूत हुई है। ये सब इस बात की बानगी है कि संकट कितना गहराया हुआ है। लेकिन इससे भी बुरी बात ये है कि संकट से उबारने के जो "उपाय", जैसे कि बड़े-पैमाने पर सौर प्लांट या जैवडीजल के लिए खेती आदि, योजनाओं में लाये भी जा रहे हैं उनके पीछे असल में जमीन को सस्ते में हड़पने और वित्तीकरण को बढाने की ही दृष्टि है और इनका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बड़े उद्योगपतियों के मुनाफों पर कोई आंच न आने पाए, भले ही संकट और भीषण हो जाए।

शहरी खेती क्यों?

इस तरह के गहरे संकट के बीच जरुरी है कि हम संभावनाओं के नए आयाम बनाएं। संकट को जड़ से हटाने के लिए शहरों को प्रकृति के साथ अपने सम्बन्ध को एक नए सिरे से संगठित करना होगा। शहर और आस-पास हर स्तर पर हो रही खेती में इस अतिशय ग्लोबल, वित्त-केन्द्रित, यथार्थ से दूर होते जाते वैश्विक खाद्य तंत्र का एक बुनियादी विकल्प बनने की सम्भावना है। इससे खाद्य श्रृंखला छोटी रहती है और खाद्य, ऊर्जा, और कचरा के शहरी तंत्र आपस में एक दूसरे से नजदीकी से जुड़े रहते हैं। इस तरह न सिर्फ शहर का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव कम होता है, बल्कि इससे लोग अपने जीवन और अपने भोजन पर नियंत्रण वापस ला पाते हैं। भोजन किस तरह से उगाया जा रहा है, उसमें पोषक तत्त्व कितने हैं[1]- ये जाँचकर और भोजन और स्थानीय पर्यावरण से जहरीले रसायन को हटाकर शहरी आबादी अपने भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता पर अपना सीधा अधिकार जमा सकती है। फसल में जहरीले तत्त्वों को कम करने से भोजन का प्रदूषण और खेत से पेट तक की दूरी के घटने से पर्यावरण का प्रदूषण कम किये जा सकते हैं जिसका नागरिक स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ा महत्त्व है। इसके अलावा शहरी खेती करने वालों के लिए राशन के खर्च के कम होने से उनकी प्रभावी आमदनी बढ़ जाती है[2]। इसलिए अगर ऐसे प्रयासों का नगर पालिका और शहर क्षेत्र के स्तर पर समन्वय किया जाए तो शहरी क्षेत्र अपने भोजन, जल, जमीन, ऊर्जा, रोजगार और ज्ञान को लेकर अधिक आत्म-निर्भर हो सकेगा। शहरों में मोहल्ला स्तर पर इसके बहुत से छिपे हुए प्रभाव हो सकते हैं। अगर क्षेत्रीय स्तर पर सामुदायिक खेती की जाए और उसके उत्पादों (और लोगों के घरों में उगाये हुए उत्पादों) को वितरित करने के लिए स्थानीय बाजार लगाया जाए तो लोगों के बीच आपस में सम्बन्ध और शहरी सामुदायिकता की भावना बढ़ेगी। शहरी खेती शहर के तनावग्रस्त माहौल से पार पाने और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद कर सकती है और शहर भर की सेहत में योगदान कर सकती है[3]।

हम यह स्पष्ट करते चलें कि कि शहरी खेती से हमारा मतलब काफी व्यापक परिवेशों में प्रयोग की जा रहीं विविध पद्धतियों[4] से है, जो अपने उद्देश्य, प्रक्रियाओं और फीडबैक चक्र के मामले में काफी अलहदा हो सकती हैं। इसमें शहरों और आस-पास खेतों में, घरों की छतों पर और आँगन/उद्यान वगैरह में की जा रही खेती के साथ-साथ मुर्गीपालन, डेयरी, पशुधन, रेशम, जल खेती (नदी, तालाब या अन्य जल निकायों में पौधे और जंतुओं का उत्पादन) सहित आजीविका के अन्य स्वरुप शामिल हैं। शहरी कृषि

---

[1] For example, all the developing regions of the world fall short of the 400 g daily intake of fruits and vegetables as recommended by FAO-WHO in WHO (2003) Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. WHO Technical Report Series no. 916. WHO, Geneva.

[2] Tambwe, N., Rudolph, M., & Greenstein, R. (2011). "Instead of begging, I farm to feed my children": Urban agriculture—An alternative to copper and cobalt in Lubumbashi. *Africa*,*81*(3), 391-412.

[3] Taylor, L., Hahs, A. K., & Hochuli, D. F. (2018). Wellbeing and urban living: nurtured by nature. *Urban Ecosystems*, *21*(1), 197–208.

[4] Bryld, E. (2003). Potentials, problems, and policy implications for urban agriculture in developing countries. *Agriculture and Human Values*, *20*, 79–86.

के पारिस्थितिकी तंत्र में न केवल खेती के विभिन्न प्रकार शामिल हैं, बल्कि कचरे का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और मिट्टी की देखभाल के लिए कचरे से बनी खाद का इस्तेमाल भी शामिल है. इसके अलावा शहर के जल संसाधनों, चरागाह और अन्य सामूहिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, माल परिवहन तंत्र, खेत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी शहरी खेती के मुद्दे हैं. इसी तरह, भूमि संबंधों और संसाधन आवंटन में इन्साफ और उस पर इतिहासपरक दृष्टि शहरी खेती की चर्चा का केन्द्रीय मुद्दा है।

शहरी खेती की अर्थव्यवस्था के आकार और कुल पैदावार के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है लेकिन उपलब्ध शोध के अनुसार अनुमान लगायें तो शहर में खेती की जमीन और खेती की उपज से शहर की खाद्य आपूर्ति- दोनों का मौजूद आकार भी काफी महत्वपूर्ण है[5]. फिर भी शहरीकरण की मौजूदा प्रक्रियाओं के बीच घिरा होने से शहरी किसान और खेतिहर समुदाय अदृश्य और भयभीत है। कुछ नए शोधकार्यों से हाल ही में ये बात पुष्ट हुई है कि शहरीकरण के मौजूदा वैश्विक स्वरुप और शहरी खेती की स्थानीय प्रथाओं के बीच का सैद्धांतिक संबंध एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि के सभी गरीब देशों में लगभग एक जैसा है जिसकी अभिव्यक्ति भूमि अधिकार की नामौजूदगी, खेती का अवैध घोषित होना, आवास और अन्य बुनियादी अधिकारों की नजरंदाजी और वित्तकेन्द्रित शहरीकरण द्वारा किसान की आजीविका निगले जाने के रूप में होती है[6]। एक विश्वव्यापी अनुमान के अनुसार, लगभग 20-30 प्रतिशत शहरी निवासी कृषि-खाद्य क्षेत्र में पहले से ही शामिल हैं। उतना ही दिलचस्प तथ्य यह है कि महिलाएं वैश्विक शहरी कृषि समुदाय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं[7], और अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी किसान ज्यादातर महिलाएं हैं। साथ ही, यह खाद्य सुरक्षा का सबसे सस्ता स्रोत है और शहरी गरीबों के लिए गरिमापूर्ण और सार्थक आजीविका के कुछ चुनिन्दा विकल्पों में से एक है. कई जगहों पर शहरी कृषि ने खेत से पेट तक भोजन की दूरी[8] और कोल्ड स्टोरेज में ऊर्जा के उपयोग को कम करके शहरी ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता दिखाई है. यही नहीं, छत पर खेती का एक फायदा ये भी दिखा है कि इमारतों में एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता कम हुई है[9] और इस तरह से 'हीट आइलैंड' प्रभाव पर कुछ काबू पाया गया है[10]। शोध में ये भी पता चला है कि भारत में छत पर खेती अन्य प्रकार के शहरी भूमि उपयोग की तुलना में उच्च जैव विविधता दिखा सकती है[11]। इस तरह के स्पष्ट लाभ के कारण इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दुनिया भर के शहर अपनी योजनाओं में शहरी खेती को शामिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापान में टोक्यो की शहर में इमारतों की छत के 20% से अधिक (और बड़ी इमारतों की छत के 30% से अधिक) हिस्से पर पेड़-पौधे उगाना अनिवार्य है[12]। यह भी गौरतलब है कि एशिया के उत्तर-पूर्वी इलाके के शहरों (उदाहरण के लिए, हनोई[13]) और अफ्रीका के शहरों (उदाहरण के लिए, नैरोबी, कंपाला[14]) ने शहरी

---

[5] Boyer, D., Sarkar, J., & Ramaswami, A. (2019). Diets, Food Miles, and Environmental Sustainability of Urban Food Systems: Analysis of Nine Indian Cities. Earth's Future, (August), 2018EF001048.

[6] For example, see: Diehl, J. A. (2019). Mapping social networks of urban farmers: A comparison of four case cities in developing versus developed countries in Asia. In ISPM PPGIS Conference. Espoo, Finland.

[7] Orsini, F., Kahane, R., Nono-Womdim, R., & Gianquinto, G. (2013). Urban agriculture in the developing world: A review. *Agronomy for Sustainable Development*, *33*(4), 695–720.

[8] Michael, M. B., & Bernhard, B. (2005). Food miles for thought. Environmental Science and Pollution Research, 12(3), 125–127.

[9] Rajesh, B. T., & Yuji, M. (2008). Land evaluation for peri-urban agriculture using analytical hierarchical process and geographic information system techniques: A case study of Hanoi. Land Use Policy, 25(2), 225–239.

[10] Dubbeling, M., Campbell, M.C., Hoekstra, F., and van Veenhuizen, R., 2009. Building Resilient Cities. Urban Agriculture Magazine, 22. June 2009.

[11] Jaganmohan, M., Vailshery, L. S., Gopal, D., & Nagendra, H. (2012). Plant diversity and distribution in urban domestic gardens and apartments in Bangalore, India. *Urban Ecosystems*, *15*(4), 911–925. https://doi.org/10.1007/s11252-012-0244-5

[12] Lee, G. G., Lee, H. W., & Lee, J. H. (2015). Greenhouse gas emission reduction effect in the transportation sector by urban agriculture in Seoul, Korea. *Landscape and Urban Planning*, *140*, 1–7.

[13] Lee, B., Binns, T., & Dixon, A. (2010). The Dynamics of Urban Agriculture in Hanoi, Vietnam. *Field Actions Science Reports*, (Special Issue 1), 1–8.

[14] (i) Karg, H., & Drechsel, P. (Eds.). (2018). *Atlas of West African urban food systems: examples from Ghana and Burkina Faso*.
(ii) Prain, G., Karanja, N., & Lee-Smith, D. (Eds.). (2010). *African Urban Harvest*. Lima, Peru: Springer in collaboration with International Potato Center (CIP) and International Development Research Centre (IDRC).

कृषि की नीतियाँ सफलता से विकसित की हैं। पेट्रोलियम आपूर्ति निरस्त होने और सोवियत संघ के कमजोर होकर विघटित हो जाने के बाद बदलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रिश्तों से क्यूबा पर घोर खाद्य संकट आ गया था[15] जिसके जवाब में वहाँ नागरिकों में सरकार की मदद से शहरी खेती पर केन्द्रित खाद्य सुरक्षा को कायम किया. दुर्भाग्य है कि गरीब देशों के लोगों और सरकारों के इन प्रयासों की हमारे नीतिकारों ने न कोई समीक्षा की, न ही योजना बनाने वालों का इस तरफ ध्यान गया.

दुखद यह भी है कि व्यवस्थागत समर्थन के अभाव में और शहरी नीति निर्माताओं की अनिच्छा के कारण, शहरी कृषि आज "अवैध" है[16] और यह ऐसी प्रवृत्ति है जो वैश्विक दक्षिण के सभी शहरों में व्याप्त है[17]। शहरी खेती के ये क्षेत्र, चाहे वह शहरी गाँवों के खेतों में हों या छत/आँगन के बगीचों में, ये सभी एक नुकसानदेह शहरीकरण के रेगिस्तान के बीच नखलिस्तान सरीखे हैं जहां शहरी जीवन प्रकृति के साथ नजदीक के संबंधों से बंधा और गढ़ा हुआ है. अब समय आ गया है कि शहरी खेती का समुदाय का एक बड़े पैमाने पर संगठित हो और साथ मिलकर हमारे बंजर होते शहरों में इस नखलिस्तान के फैलाव के तरीके तलाश करे।

---

[15] Koont, S. (2011). *Sustainable urban agriculture in Cuba*. University Press of Florida.
[16] Cook, J., Oviatt, K., Main, D. S., Kaur, H., & Brett, J. (2015). Re-conceptualizing urban agriculture: an exploration of farming along the banks of the Yamuna River in Delhi, India. *Agriculture and Human Values*, *32*(2), 265–279.
[17] Maxwell, D. G. (1995). Alternative food security strategy: A household analysis of urban agriculture in Kampala. *World Development*, *23*(10), 1669–1681.

आयोजक

जन संसाधन केंद्र का लक्ष्य सामाजिक आन्दोलनों से प्राप्त मूल्यवान सीखों और संभावित विकल्पों को लेकर सब लोगों की कल्पनाओं को साथ लाकर एकजुटता का नया आधार बनाना है। यह पहल संसाधनों पर लोगों का नियंत्रण वापस लाने की संभावनाएँ बनाने के लिए, और यह समझने के लिए की गयी है कि कैसे इस जरिये भूख, बेघरी, प्रदूषण, और जाति, लिंग, धर्म पर टिके सामाजिक अन्याय का उन्मूलन कर सकते हैं। हम संसाधनों के हक़ के इर्द-गिर्द हो रहे (या संभावित) संघर्ष में आंदोलन समूहों और समुदायों के साथ जुड़कर योगदान करते हैं। सामूहिक प्रतिरोध और रचनात्मक कार्यक्रम के लिए संसाधन उत्पन्न करने के उद्देश्य से हम नियमित रूप से नीतियों की निगरानी, शोध, प्रकाशन और जमीनी स्तर पर नेटवर्किंग के उपाय करते हैं।

संपर्क: prc.india@yahoo.com

इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी पिछले तीन दशकों से टिकाऊ शहरी परिवहन, समान सड़क अधिकार, आजीविका के अधिकार और शहर में खेती समेत सामाजिक परिवर्तन के कई मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करता रहा है। हमारे अनुसार पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, एक जिंदादिल शहर को विकसित करने की शर्त है कि रोजगार, आवास और शिक्षा के लिए गुणवत्ता और समता के मूल्यों पर आधारित अवसर उपलब्ध कराये जायें। हमारा मानना है कि इसके लिए स्थानीय और विकेन्द्रीकृत उत्पादन और वितरण प्रणाली को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी नेटवर्क ऑफ इंडिया (SUMNet), कार-फ्री नेटवर्क आदि के एक घटक सदस्य हैं और विविध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़े हुए हैं।

संपर्क: idsinitiative@gmail.com

तकनीकी सहयोग

ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजुरी प्रिवेंशन प्रोग्राम (ट्रिप-TRIPP), आइआइटी दिल्ली सड़क यातायात के बुरे स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के उपायों पर शोध करने एक साझा कार्यक्रम है. ट्रिप के शोधकार्यों और आयोजनों का उद्देश्य यातायात से जुड़े सभी मुद्दों को एक साथ लाकर सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और ऊर्जा संचय को बढ़ावा देना है.